

सचिन गर्ग

बनाम

उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 497/2024)

30 जनवरी 2024

[न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार]

विचारार्थ मुद्दा

ऐसे मामले में जहां विवाद वाणिज्यिक प्रकृति का था, जिसमें आपराधिकता का कोई तत्व नहीं था, क्या मजिस्ट्रेट को दंड संहिता, 1860, धारा 406, 504 और 506 के तहत मुकदमे के लिए समन जारी करना उचित था और उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सम्मन और शिकायत मामले को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज करना उचित था।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – समन जारी करना, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य – दंड संहिता, 1860– धारा.406, 504 और 506 – व्यावसायिक विवाद को दिया गया आपराधिक रंग – जिस दर पर सौंपा गया काम किया जाना था, उससे संबंधित पक्षों के बीच विवाद – प्रतिवादी नंबर 2 ने शिकायत दर्ज कराई – मजिस्ट्रेट द्वारा आईपीसी की धारा 406, 504 और 506 के तहत मुकदमे के विचारण के लिये सम्मन जारी किया गया – समन और शिकायत मामले को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया – औचित्य:

अवधारित किया गया: अपीलकर्ता के नियोक्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच पिछले वाणिज्यिक संबंध को स्वीकार किया गया था – पार्टियों के बीच विवाद उस दर के आसपास केंद्रित था जिस पर सौंपा गया काम किया जाना था – न तो शिकायत याचिका में और न ही दो गवाहों के प्रारंभिक बयान में (शिकायतकर्ता सहित), आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध की सामग्री सामने आई – दर में भिन्नता पर ऐसे वाणिज्यिक विवाद किसी भी उत्तेजक कारक की उपस्थिति के बिना आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसके अवयवों के बारे में – ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकले कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए गैस आपूर्ति कार्य के संबंध में अपीलकर्ता के व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी सामग्री का बेईमानी से दुरुपयोग या रूपांतरण किया गया था – उक्त कार्य में नियमित वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान किया गया था – ईआईएल में बैटरी निर्माण के उद्देश्य से कारखाने को आपूर्ति की गई विघटित एसिटिलीन गैस की विषय संपत्ति का कोई दुरुपयोग या रूपांतरण नहीं हुआ था। – आईपीसी की धारा 405/406 के तहत अपराध के कमीशन के लिए कोई सबूत नहीं – इसके अलावा, आपराधिक धमकी के संबंध में भी महज एक आरोप था, जिसमें धमकी देने के तरीके के बारे में कोई विवरण नहीं था – जबकि यह सच है कि समन जारी करने के चरण में एक मजिस्ट्रेट को केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया मामले में, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य यह भी संतुष्ट होना है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं – मजिस्ट्रेट का समन जारी करने का आदेश गुप्त तरीके से उसकी संतुष्टि को दर्शाता है – समन जारी करने के चरण में, हालांकि विस्तृत तर्क यह है कि क्यों मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप उन अपराधों को जन्म नहीं देते हैं जिनके लिए अपीलकर्ता को सुनवाई के लिए बुलाया गया था – एक वाणिज्यिक विवाद, जिसे फोरम के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था दंड संहिता से कुछ शब्दों या वाक्यांशों को हटाकर और उन्हें आपराधिक शिकायत में शामिल करके सिविल कोर्ट को आपराधिक रंग दिया गया – मजिस्ट्रेट समन जारी करने में अपना विवेक लगाने में विफल रहे और उच्च न्यायालय धारा 482, 1973 संहिता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा। – आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया, शिकायत और सम्मन आदेश रद्द कर दिया गया। [पैरा 14, 17 और 18]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – क्षेत्राधिकार – चर्चा की गई।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत मामले में आईपीसी की धारा 406, 504 और 506 के तहत मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया – अपीलकर्ता ने इस आधार पर शिकायत को खारिज करने की मांग की कि शिकायत नहीं होनी चाहिए थी मुख्य कंपनी पर आरोपी के रूप में आरोप लगाए बिना विचार किया गया:

अवधारित किया गया: कथित गलत कार्य के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया था, हालांकि शिकायत याचिका स्वीकार करती है कि नौकरी-कार्य ईआईएल (अपीलकर्ता के नियोक्ता) के लिए किया जा रहा था – इसके अलावा, आपराधिक धमकी का आरोप सीधे अपीलकर्ता के खिलाफ था, चाहे इस आरोप का मूल्य या गुणवत्ता कुछ भी हो – इस प्रकार, इस कारण से कंपनी को शामिल न करने के एकमात्र आधार पर प्रारंभिक चरण में शिकायत मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है – हालांकि, दिए गए कारणों से शिकायत और सम्मन रद्द कर दिया गया। [पैरा 20]

विधि वाद सन्दर्भ

शरद कुमार संघी बनाम संगीता राने[2015] 2 एससीआर 145: (2015) 12 एससीसी 781 – अनुपयुक्त ठहराया गया।

जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य[2004] 2 एससीआर 846: (2004) 4 एससीसी 432 – पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अवलम्ब लिया गया।

निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य.,[2021] 4 एससीआर 1044: (2021) 19 एससीसी 401; आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, [1960] 3 एससीआर 388: वायु (1960) एससी 866; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य.,[1992] पूरक। (3) एससीआर 735:(1992) एससीसी(सीआर) 426; बिहार राज्य और अन्य. बनाम पी. पी. शर्मा, आईएसओर अन्य,[1991] 2 एससीआर 1:(1992) एससीसी (सीआर) 192; झंडुफार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम मो शरफुलहक और अन्य[2004] एसयूपीपीएल. (5) एस.सी.आर. 790:(2005)एससीसी (सीआर) 283; दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर राज्यप्रदेश और अन्य(2023) 3 एससीसी 423; प्रो. आर.के.विजयसार्थी और अन्य. बनाम सुधा सीतारम और अन्य।[2019] 2 एससीआर 185: (2019) 16 एससीसी 739; विजय कुमार घई और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।[2022] 1 एससीआर 884:(2022) 7 एससीसी 124; दलीप कौर और अन्य बनाम जगनार सिंह और अन्य.,[2009] 10 एससीआर 264: (2009) 14 एससीसी 696; बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंट्रज इन्वेस्टमेंट्स और होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य.,[2019] 7 एससीआर 655: (2019)16 एससीसी 610; श्रीमती नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पाकोन्जाल्नी और अन्य[1976] 1 एसयूपीपीएल एससीआर 123: (1976) 3 एससीसी 736; फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक और,[2013] 9 एससीआर 240: (2013) 14 एससीसी 44; बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य,[2014] 11 एससीआर 85: (2014) 10 एससीसी 663; पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य. बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य,[1997] 5 एसयूपीपीएल. एससीआर 12: (1998) 5 एससीसी 749 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860.

मुख्य शब्दों की सूची

वाणिज्यिक विवाद; आपराधिक रंग; सम्मन जारी करने का चरण; मजिस्ट्रेट का कर्तव्य; रद्द करना; सम्मन को रद्द करना; व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामग्री का बेईमानी से दुरुपयोग/रूपांतरण; आपराधिक धमकी; मन का प्रयोग न करना; प्रमुख कंपनी को फंसाया नहीं गया.

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 497/ 2024।

अनुच्छेद 482 के आवेदन संख्या – 18603/2021 के में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.03.2023 से।

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता – मुकुल रोहतगी, गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री. मिशा रोहतगी, सुशील शुक्ला, नकुल मोहता, कु. अलीना मेरिन मैथ्यू, मुथु थंगथुराई।

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता – सर्वेश सिंह बघेल, अविरल सक्सैना, अरुण प्रताप सिंह राजावत, कु. वंशजा शुक्ला, कु. दिव्य ज्योति सिंह, कु. अंकिता अपन्ना, मनीष गुप्ता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

अनुमति प्रदान की गयी

2. अपीलकर्ता, तात्विक बिंदु पर, हरियाणा के बावल, जिला रेवाड़ी में स्थित एक कॉर्पोरेट इकाई, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("ईआईएल") के कारखाने के प्रमुख के रूप में तैनात था। प्रतिवादी नंबर 2, एक मालिकाना कंपनी, अंबिका गैसेस चलाती थी। वह डिऑल्व्ड एसिटिलीन गैस ("डीए गैस") का आपूर्तिकर्ता था, जिसका उपयोग उक्त कारखाने में बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। जहां तक वर्तमान अपील का सवाल है, विवाद उक्त वस्तु की आपूर्ति के लिए जारी किए गए खरीद आदेश पर है। मूल खरीद आदेश दिनांक 01.04.2019 को प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर दो बार संशोधित किया गया था। पहला संशोधन 18.07.2019 को किया गया जिसके द्वारा दर 1.55 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 1.65 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई और दूसरा संशोधन 20.12.2019 को किया गया जिसके माध्यम से 1.65 रुपये प्रति यूनिट दर 1.48 रुपये कर दी गई। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उपरोक्त दरों के साथ कुल 9,36,693.18/- रुपये का चालान पेश किया गया था। विवाद उक्त राशि का भुगतान न करने को लेकर है। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ईआईएल ने अन्य विक्रेताओं से डीए गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के बाद, दिनांक 29.06.2020 के एक पत्र द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 को सूचित करके खातों का मिलान किया कि उसने जो दावा किया था वह दरों की गणना के संशोधन के संबंध में बेईमानी थी और चालान से विक्रेता (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दावा की गई कथित अवैध राशि को विनियोजित किया।

3. प्रतिवादी नंबर 2 ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अदालत में एक शिकायत मामला दायर किया और शिकायत का सार शिकायत की याचिका (प्रकीर्ण आवेदन संख्या 317/2020 के रूप में पंजीकृत) के निम्नलिखित अंशों को समक्षने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

"...आवेदक अपने उपरोक्त कार्य के माध्यम से डी.ए. गैस में कार्य करता है। विपक्षी सचिन गर्ग प्लॉट नंबर 179, सेक्टर-3, बावल, जिला-रेवाड़ी, हरियाणा में स्थित एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मटेरियल हेड के रूप में तैनात हैं और विपक्षी सचिन गर्ग आवेदक की कंपनी की ओर से खरीद आदेश भी जारी करते थे। एक्साइड कंपनी और केवल विपक्षी सचिन गर्ग आवेदक को जॉब वर्क का भुगतान करते थे। पहले, आवेदक की कंपनी के साथ विपक्षी पार्टी का लेनदेन सामान्य था और भुगतान में कभी कोई समस्या नहीं आई, जिसके कारण आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को विपक्षी पार्टी और कंपनी पर भरोसा होने लगा। सचिन गर्ग ने क्रय प्रमुख की हैसियत से उपरोक्त कंपनी के माध्यम से आवेदक की कंपनी को क्रय आदेश जारी किया, जिसमें विपक्षी और आवेदक के बीच 1.65/- रुपये प्रति नग की दर से जॉब वर्क करने पर सहमति बनी। जो दिनांक 18.02.2019 से दिसम्बर 2019 तक उसी दर पर जारी रहा तथा विपक्षी द्वारा आवेदक को जॉब वर्क का भुगतान नियमित रूप से उसी दर पर किया जा रहा था। दिसम्बर माह में विपक्षी के क्रय आदेश के अनुसरण में क्रय क्रमांक 4800253593 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार फिल्ड डीए गैसेस एचएसएन कोड 290129910 मात्रा 3,07,114/- नग 165 रुपये की दर से रु.5,06,738.10/- रुपये निर्धारित किया गया, और भरे हुए डीए गैस एचएसएन कोड 29012910 की मात्रा 1,93,966/- रु. 1.48 प्रति नग की दर से रु. 2,87,069.68/- एवं 18% जीएसटी के साथ रुपये 1,42,885.40/-, इस प्रकार कुल राशि रुपये 9,36,693.18/- का कार्य किया गया। विपक्षी कंपनी के मटेरियल हेड सचिन गर्ग ने क्रेता आदेश संख्या 4800253593 दिनांक 01.04.2019 के तहत आवेदक द्वारा किए गए जॉब वर्क को स्वीकार करते हुए आवेदक द्वारा उद्धृत पीस रेट के अनुसार जॉब वर्क करवाया। 03.07.2020 को आवेदक के द्वारा भेजा गया बिल/चालान संख्या AG.SR/20-21/01 दिनांक 02.07.2020 रुपये 9,36,693.18/- का विपक्षी कंपनी के सामग्री प्रमुख सचिन गर्ग को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा और उपरोक्त चालान भी 14.07.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजा। जो विपक्षी सचिन गर्ग को प्राप्त हुआ। आवेदक ने बार-बार विपक्षी पार्टी को ईमेल के माध्यम से भुगतान के लिए अनुरोध किया, लेकिन, विपक्षी पार्टी ने आवेदक कंपनी द्वारा दिसंबर, 2019 के महीने में किए गए जॉब वर्क के 9,36,693.18/- रुपये का भुगतान नहीं किया और उसने आवेदक को अधरे में रखा, पूरा भुगतान करने का आश्वासन देता रहा। जब, आवेदक ने भुगतान के लिए विपक्षी पर अधिक दबाव डाला, तो, विपक्षी ने आवेदक कंपनी से जॉब वर्क कराना बंद कर दिया और दिनांक 29.06.2020 को आवेदक कंपनी को कोटेशन के साथ एक पत्र भेजा, जिसमें, विपक्षी पार्टी ने आवेदक कंपनी द्वारा किये गये जॉब वर्क की दर 1.40/- रुपये प्रति नग निर्धारित की है। अप्रैल, 2019, जबकि आवेदक कंपनी द्वारा विपक्षी का जॉब वर्क माह दिसंबर, 2019 में पूरा कर लिया गया था, जिसमें विपक्षी ने दिनांक 20.12.2019 को जॉब वर्क की दर में परिवर्तन कर रु. 1.48/- प्रति पीस, जिसे आवेदक द्वारा 1.4.2018 से स्वीकार किया गया था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा दिनांक 20.12.2019 के बाद रुपये 1.48/- प्रति नग एवं उसके पूर्व रुपये 1.65/- प्रति नग की दर से भुगतान देय था, परन्तु विपक्षी द्वारा जानबूझकर आवेदक को धोखा देने की नियत से तरीके से, और उसे वित्तीय नुकसान पहुंचाने और पैसे का भुगतान न करने के इरादे से, आवेदक के साथ आपराधिक विश्वासघात किया है, जो एक संज्ञेय अपराध है। आवेदक द्वारा पैसे मांगने पर विपक्षी उसे गंदी-गंदी गालियां दे रहा है तथा जान से मारने की धमकी दे रहा है..."

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(पेपर बुक से शब्दशः उद्धृत)

4. विद्वान मजिस्ट्रेट ने आपूर्तिकर्ता फर्म के मालिक सौरभ शर्मा और उनके पिता पदम कांत शर्मा का प्रारंभिक बयान दर्ज करने के बाद 18 अगस्त 2021 को भारतीय दंड संहिता, 1860 ("1860 कोड") की धारा 406, 504 और 506 के तहत मुकदमे के लिए समन जारी किया।

5. अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("1973 संहिता") की धारा 482 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उक्त समन और शिकायत मामले को भी रद्द करने के लिए आपराधिक विविध आवेदन संख्या 18603/2021 दाखिल करके। 23.03.2023 को अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया और यही निर्णय हमारे समक्ष अपील के अधीन है। अपीलकर्ता की रद्द करने की याचिका को खारिज करने का मुख्य कारण यह था कि विषय-शिकायत में तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्णय शामिल था। निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड -बनाम- महाराष्ट्र राज्य और अन्य। [(2021) 19 एससीसी 401], आर.पी. कपूर -बनाम- पंजाब राज्य [एआईआर 1960 एससी 866], हरियाणा राज्य और अन्य. -बनाम- भजन लाल और अन्य। [1992 एससीसी (सीआर) 426], के राज्य बिहार और अन्य. -बनाम- पी. पी. शर्मा, आईएस और अन्य। [1992 एससीसी (सीआर) 192] और अंत में झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य -बनाम मो. शरफुल हक और अन्य [2005 एससीसी (सीआर) 283], के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के बचाव पर विचार करने से परहेज किया।

6. निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उन कारकों की जांच की जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए विचार किया जाना था। सीमा पर, उन कारकों से संबंधित जो उस कार्यवाही पर लागू होंगे जो विषय का निर्माण करती है मौजूदा मामले की बात. आर.पी. कपूर (उपरोक्त) के मामले में फैसले का जिक्र कर रहे हैं, रद्द करने के सिद्धांत इस प्रकार निर्धारित किए गए थे: -

"10.1 जिस बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है उस पर पहला मामला c8 आर.पी. कपूर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है कि उपरोक्त संहिता की धारा 561-ए (जो कि संहिता की धारा 482 के बराबर है) के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से निपटते समय, यह देखा और माना जाता है कि धारा 561 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां संहिता के अन्य प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से कवर किए गए मामलों के संबंध में पिछली संहिता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है; किसी उचित मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जा सकता है; आम तौर पर किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को संहिता के प्रावधानों के तहत चलाया जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय अंतरिम चरण में उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। इसका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अवलोकन करने के बाद, इसके बाद इस न्यायालय ने उपरोक्त नियम में कुछ अपवाद निकाले, जो इस प्रकार हैं:

“(i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कथित अपराध के संबंध में संस्था के खिलाफ या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने में कोई कानूनी बाधा है। उदाहरण के लिए, अपेक्षित मंजूरी के अभाव में इस श्रेणी के अंतर्गत मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं; ऐसे मामलों में साक्ष्य की सराहना का कोई सवाल ही नहीं उठता; यह केवल शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने का मामला है ताकि यह तय किया जा सके कि कथित अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

(iii) जहां आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप कथित अपराध का गठन करते हैं लेकिन मामले के समर्थन में या तो कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया गया है या लगाए गए सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल हैं। मामलों के इस वर्ग से निपटने में ऐसे मामले के बीच अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या जहां ऐसे सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोप के साथ असंगत हैं और ऐसे मामले जहां कानूनी सबूत हैं जो अपने अवलोकन के आधार पर प्रश्नगत आरोप का समर्थन कर भी सकता है और नहीं भी। धारा 561-ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। यह ट्रायल मजिस्ट्रेट का कार्य है, और आमतौर पर यह किसी भी पक्ष के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करने और यह तर्क देने के लिए खुला नहीं होगा कि सबूतों की उचित सराहना के बावजूद आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं पाएंगे।

7. उसी निर्णय में (अर्थात् निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड.) (उपरोक्त), भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित सात सूत्री आदेश का भी उल्लेख किया गया था। ये हैं:—

“102.(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही वे अपने स्तर पर लिए गए हों अंकित मूल्य और पूरी तरह से स्वीकार किए जाने से प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 155(2) के दायरे में आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संबंधित संहिता या अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

8. अपील के तहत फैसले में यह देखा गया कि आवेदक को मुक्ति का अधिकार मिला है जिसे वह विचारण न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र रूप से ले सकता है। इस मामले में अपीलकर्ता की ओर से श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री गुरु कृष्ण कुमार के साथ उपस्थित हुए हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के मामले में सुश्री दिव्य ज्योति सिंह द्वारा बहस की गई है। हमारे समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व श्री सर्वेश सिंह बघेल ने किया। श्री रोहतगी द्वारा आग्रह किया गया मुख्य तर्क यह है कि अपीलकर्ता के खिलाफ की गई शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है और सबसे अच्छा, यह एक वाणिज्यिक विवाद है, जिसे सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। जहां तक धारा 405 और 406 के तहत अपराध करने के आरोपों का सवाल है, उन्होंने दीपक गाबा और अन्य –बनाम– उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[(2023) 3 एससीसी 423] मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। यह निर्णय 1860 संहिता की धारा 405 और 406 के तहत शिकायत के मूल तत्वों से संबंधित है और इसे इस निर्णय में अवधारित किया गया है: –

“15. आईपीसी की धारा 405 को लागू करने के लिए, निम्नलिखित को स्थापित करना होगा:

(ए) अभियुक्त को संपत्ति सौंपी गई थी, या संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया था;

(बी) आरोपी ने बेईमानी से गड़बड़ी की थी और उस संपत्ति को अपने स्वामित्व में ले लिया या अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लिया, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान किया गया जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कष्ट देना; और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(सी) इस तरह का दुरुपयोग, रूपांतरण, उपयोग या निपटान कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन होना चाहिए जो उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसे ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन होना चाहिए जो व्यक्ति ने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन को छूते हुए किया है।”

9. दीपक गाबा(उपरोक्त) का निर्णय एक ऐसे मामले में दिया गया था जिसमें पार्टियों के बीच वाणिज्यिक संबंध मौजूद थे और शिकायतकर्ता ने लगभग साढ़े छह लाख रुपये की जाली मांग का आरोप लगाया था। उस आधार पर 1860 संहिता की धारा 406 के तहत मुकदमे के लिए सम्मन आदेश जारी किया गया था। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अवधारित किया था कि:-

“17. हालाँकि, मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आईपीसी की धारा 405 की सामग्री को संतुष्ट करने में विफल रहती है। शिकायत सीधे तौर पर धारा 405 आईपीसी की सामग्री का उल्लेख नहीं करती है और यह नहीं बताता कि कैसे और किस तरीके से, तथ्यों के आधार पर, आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सम्मन-पूर्व साक्ष्य का भी अभाव है और इस कारण नुकसान होता है। इन पहलुओं पर, समन आदेश समान रूप से शांत है, हालाँकि, इसमें कहा गया है कि “जेआईपीएल द्वारा 6,37,252.16 रुपये की जाली मांग की गई थी, जो कि शुभंकर पी. तोमर और साक्षी तिलक चंद के बयानों के अनुसार मांग नहीं है।” महज एक गलत मांग या दावा, सौंपे जाने, बेईमानी से किए गए दुरुपयोग, रूपांतरण, उपयोग या निपटान को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के अभाव में धारा 405 आईपीसी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करेगा, कौन सा कार्य कानून के किसी निर्देश, या विश्वास के निर्वहन से संबंधित कानूनी अनुबंध का उल्लंघन होना चाहिए। इसलिए, भले ही प्रतिवादी 2 शिकायतकर्ता की राय है कि मौद्रिक मांग या दावा गलत है और देय नहीं है, धारा 405 आईपीसी की आवश्यकताओं को साबित करने में विफलता को देखते हुए, उसी धारा के तहत अपराध नहीं बनता है। धारा 405 आईपीसी के तहत अपराध की सामग्री को संतुष्ट करने वाले तथ्यात्मक आरोपों के अभाव में, 6,37,252.16 पी रुपये की मौद्रिक मांग पर मात्र विवाद, धारा 406 आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाएगा।

10. इस न्यायालय द्वारा के मामलों में भी यही विचार व्यक्त किया गया था प्रो आर.के. विजय सारथी और अन्य. -बनाम- सुधा सीतारम और अन्य। [(2019) 16 एससीसी 739] और विजय कुमार घई और अन्य। -बनाम- राज्य पश्चिम बंगाल और अन्य के। [(2022) 7 एससीसी 124]। के मामले में इस न्यायालय का निर्णय Dalip Kaur and Ors. -vs- Jagnar Singh और अन्य। [(2009) 14 एससीसी 696] को अपीलकर्ता के मामले के समर्थन में भी उद्धृत किया गया है और इस निर्णय में, अन्य बातों के अलावा, यह माना गया है: -

“10. इसलिए, उच्च न्यायालय को यह प्रश्न उठाना चाहिए था कि क्या अपीलकर्ता की ओर से किसी प्रलोभन का कार्य दूसरे प्रतिवादी द्वारा उठाया गया है और क्या अपीलकर्ता का शुरु से ही उसे धोखा देने का इरादा था। यदि पार्टियों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से एक नागरिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विवाद था, जो अग्रिम राशि वापस न करने पर अपीलकर्ताओं की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ था, तो यह धोखाधड़ी का अपराध नहीं होगा। दंड संहिता की धारा 405 में निहित परिभाषा के संबंध में आपराधिक विश्वासघात के अपराध के संबंध में कानूनी स्थिति भी ऐसी ही है। यह 1860 संहिता की धारा 406 से संबंधित आरोपों के लिए जाता है।

11. जहां तक 1860 संहिता की धारा 504 और 506 के तहत अपराध करने के आरोपों का सवाल है, हमने शिकायत याचिका के साथ-साथ प्रारंभिक बयानों का भी अध्ययन किया है। 1860 संहिता के उपरोक्त प्रावधानों से संबंधित आरोप शिकायत याचिका के अंतिम भाग में सामने आते हैं। शिकायतकर्ता ने अपने प्रारंभिक बयान में आपराधिक धमकी से संबंधित कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके पिता ने उस समय 1973 संहिता की धारा 202 के तहत निम्नलिखित बयान दिया:—

“... 18.07.2019 से, विपक्षी पार्टी ने मेरे बेटे की कंपनी के साथ जॉब वर्क की दर 1.65/- रुपये प्रति पीस तय की थी, जो दिसंबर, 2019 तक जारी रही और विपक्षी पार्टी जॉब वर्क का भुगतान करती रही मेरे बेटे को भी इसी दर पर और 9,36,693.18/- रु. मेरे बेटे का भुगतान विपक्षी पार्टी पर बकाया था, जिसके कारण उसने विपक्षी से भुगतान करने की मांग की, लेकिन, विपक्षी ने भुगतान नहीं किया और कम दरों पर गणना करने के बाद कहा कि नहीं रकम का भुगतान बाकी है और रकम मांगने पर विपक्षी ने मेरे बेटे को गंदी-गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी है। मेरे बेटे का 9,36,693.18/- रुपये की राशि विपक्षी पार्टी पर बकाया है, जिसे देने से उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।”

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

12. शिकायतकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि जिस स्तर पर अपीलकर्ता शिकायत को अमान्य करना चाहता है, उस स्तर पर अपमानजनक कृत्यों का विस्तृत विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य[(2004) 4 एससीसी 432]। इस निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है:—

“10... . यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुलिस की राय के बावजूद, एक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री उक्त उद्देश्य के लिए मामला बनाती है। जांच पुलिस का विशेष क्षेत्र है। अपराध का संज्ञान लेना विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का क्षेत्र है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, न कि दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं, यह केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है, पूछताछ के चरण में नहीं। अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड –बनाम– एडवेंट्रज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। और अन्य.[(2019) 16 एससीसी 610] भीश्रीमती नागव्वा –बनाम– वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोन्जाल्मी और अन्य[(1976) 3 एससीसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

736] उक्त मामले में भी इसी तरह के विचार इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये हैं।

13. जहां तक आपराधिक धमकी के आरोपों का सवाल है, हमारा ध्यान फियोना श्रीखंडे – बनाम – महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2013) 14 एससीसी 44] के मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया गया है। इस मामले में यह माना गया है कि शिकायत की याचिका में वास्तविक शब्दों या अपमान की भाषा को शब्द दर शब्द दोहराने की आवश्यकता नहीं है और शिकायत को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जानबूझकर अपमान किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाया जा सके तो यह शिकायत को उपरोक्त प्रावधान के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता को किसी भी स्थिति में आरोपमुक्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है और शिकायत की याचिका में कोई अपराध न होने का दोष नहीं है। यह उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण था।

14. अपीलकर्ता के नियोक्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच पिछले व्यावसायिक संबंध को स्वीकार किया गया है। शिकायत की याचिका से यह भी स्पष्ट होगा कि पक्षकारों के बीच विवाद उस दर के आसपास केंद्रित था जिस पर सौंपा गया कार्य किया जाना था। न तो शिकायतकर्ता की याचिका में और न ही दो गवाहों (जिसमें शिकायतकर्ता भी शामिल है) की प्रारंभिक गवाही में 1860 संहिता की धारा 405 के तहत अपराध की सामग्री सामने आई एवं दर में भिन्नता पर इस तरह के वाणिज्यिक विवाद 1860 संहिता की धारा 405 के तहत किसी भी उत्तेजक कारक की उपस्थिति के बिना किसी अपराध को जन्म नहीं दे सकते हैं, जिससे इसके अवयवों की पुष्टि हो सके। हमें प्रथमदृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए गैस आपूर्ति कार्य के संबंध में अपीलकर्ता के व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी सामग्री का बेईमानी से दुरुपयोग या रूपांतरण किया गया था। उक्त कार्य नियमित वाणिज्यिक लेनदेन के क्रम में किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि हेराफेरी हुई है या विषय संपत्ति का रूपांतरण, विघटित एसिटिलीन गैस जिसे ईआईएल में बैटरी निर्माण के उद्देश्य से कारखाने को आपूर्ति की गई थी। यह विवाद चल रहे वाणिज्यिक लेनदेन में प्रति यूनिट दर के संशोधन से संबंधित है। शिकायत याचिका और उसके समर्थन में किए गए प्रारंभिक बयान से जो सामने आया है वह यह है कि आरोपी – अपीलकर्ता दर में बदलाव चाहता था और पूरा विवाद अपीलकर्ता के ऐसे रुख से उत्पन्न हुआ। इन सामग्रियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 405/406 के तहत अपराध घटित होने के साक्ष्य थे। उच्च न्यायालय ने भी दिलीप कुमार (उपरोक्त) के मामले में तैयार किए गए परीक्षण को लागू नहीं किया। उस निर्णय का प्रासंगिक अंश हम पहले बता चुके हैं।

15. बिनोद कुमार और अन्य – बनाम – बिहार राज्य और अन्य [(2014) 10 एससीसी 663] के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान बिल राशि को रोके रखने से उत्पन्न एक आपराधिक शिकायत से निपटा। न्यायालय ने पाया कि विश्वास के आपराधिक उल्लंघन या प्रलोभन के बेईमान इरादे के आवश्यक तत्व गायब थे, जो शिकायत का आधार बने। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय ने रद्द कर दिया था। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का तर्क रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 और 19 से सामने आएगा, जिसमें लिखा है: –

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“18.वर्तमान मामले में, शिकायत में आरोपों को प्रथम दृष्टया देखने पर, हम पाते हैं कि आईपीसी की धारा 405 के तहत कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। इसी तरह, खुद को गलत लाभ पहुंचाने या शिकायतकर्ता को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे को अपने पास रखने में धोखाधड़ी या अपीलकर्ताओं के बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। इन बेबुनियाद आरोपों को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग स्वयं या किसी अन्य कार्य के लिए किया, संपत्ति के दुरुपयोग में बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने पैसा अपने पास रखा है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने बेईमानी से इसे किसी तरह से निपटा दिया या बेईमानी से इसे बरकरार रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासघात की श्रेणी में नहीं आता है।

19. भले ही अंकित मूल्य पर ली गई शिकायत में सभी आरोप सही हों, हमारे विचार में, बेईमानी से हेराफेरी और धोखाधड़ी के बुनियादी आवश्यक तत्व गायब हैं। आपराधिक कार्यवाही अन्य उपचारों का शॉर्टकट नहीं है। चूंकि आपराधिक विश्वासघात या प्रलोभन के बेईमान इरादे का कोई मामला नहीं बनता है और धारा 405/420 आईपीसी की आवश्यक सामग्री गायब है, धारा 406/120- बी आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं का अभियोजन रद्द किया जा सकता है।

16. जहां तक इस मामले में आपराधिक शिकायत और शुरुआती बयानों का सवाल है, तथ्यात्मक आधार मोटे तौर पर समान है। हमने इन सामग्रियों को इस फैसले में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया है। हमें नहीं लगता कि उनके पास 1860 संहिता की धारा 405 में निर्दिष्ट अपराध की सामग्री है।

17. अपीलकर्ता द्वारा दिए गए शिकायती बयानों में अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया है, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। शिकायत याचिका और गवाहों में से एक की प्रारंभिक गवाही दोनों में, आपराधिक धमकी के अपराध को जन्म देने वाले वैधानिक प्रावधान के केवल एक हिस्से का पुनरुत्पादन है। यह महज एक झूठा आरोप होगा, जिसमें धमकी देने के तरीके के संबंध में कोई विशेष विवरण नहीं होगा।

18. हालांकि यह सच है कि समन जारी करने के चरण में एक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के लिए केवल प्रथम दृष्टया मामले से संतुष्ट होने की आवश्यकता है, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य यह भी संतुष्ट होना है कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, जैसा कि जगदीश राम (उपरोक्त) के मामले में माना गया है। पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य -बनाम- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य. [(1998) 5 एससीसी 749] के मामले में भी कानून का यही प्रस्ताव रखा गया है। समन जारी करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में मामले की पृष्ठभूमि को काफी लंबे विवरण में दर्ज किया गया है, लेकिन गुप्त तरीके से उनकी संतुष्टि को दर्शाया गया है। हालांकि, सम्मन जारी करने के चरण में, एक मजिस्ट्रेट सम्मन क्यों जारी कर रहा है, इसका विस्तृत तर्क आवश्यक नहीं है। लेकिन इस मामले में, हम संतुष्ट हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप उन अपराधों को जन्म नहीं देते हैं जिनके लिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता को मुकदमे के लिए बुलाया गया है। एक वाणिज्यिक विवाद, जिसे सिविल कोर्ट के मंच के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था, को दंड संहिता से कुछ शब्दों या वाक्यांशों को हटाकर और उन्हें आपराधिक शिकायत में शामिल करके आपराधिक रंग दे दिया गया है। यहां के विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा समन जारी करने में अपना विवेक लगाने में विफल रहे और उच्च न्यायालय भी आपराधिक न्यायालय की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1973 संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा।

19. यह सच है कि अपीलकर्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान ही मुक्ति की मांग कर सकता है, लेकिन यहां हम पाते हैं कि ऐसा कोई भी मामला नहीं बनाया गया है जो आपराधिक न्यायालयों की मशीनरी को लागू करने को उचित ठहरा सके। विवाद, वस्तुतः, वाणिज्यिक प्रकृति का है जिसमें आपराधिकता का कोई तत्व नहीं है।

20. अपीलकर्ता यह भी चाहता था कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए और आगामी कार्यवाही में किसी अन्य आधार पर आदेश पारित किया जाए। प्रतिवादी सं. 2 के आरोप ईआईएल पर थे, जिसके लिए उन्होंने जॉब-वर्क किया था। इस बिंदु पर अपीलकर्ता का तर्क यह है कि मुख्य कंपनी को आरोपी बनाए बिना शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इस बिंदु पर जिस निर्णय पर भरोसा किया गया वह सरद कुमार संधी बनाम संगीता राने [(2015) 12 एससीसी 781] के मामले में एक समन्वय पीठ का निर्णय है। यह एक ऐसा मामला था जहां एक उपभोक्ता द्वारा 1860 संहिता की धारा 420 के तहत क्षतिग्रस्त वाहन बेचे जाने की शिकायत की गई थी। लेकिन आरोपी के रूप में डीलर के प्रबंध निदेशक को दोषी ठहराया गया, जो एक कॉर्पोरेट इकाई थी। उस मामले में संज्ञान लिया गया और समन जारी किया गया। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के बाद आरोपी को राहत नहीं मिल पाई, लेकिन इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मुख्य रूप से इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया कि कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया था। कोऑर्डिनेट बेंच ने पाया कि आरोप उस कंपनी के खिलाफ लगाए गए थे, जिसे पार्टी नहीं बनाया गया था। आरोपी (उस कंपनी के प्रबंध निदेशक) के खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, शरद कुमार संधी (उपरोक्त) मामले में निर्णय का अनुपात अकेले इस आधार पर शिकायत को दहलीज से बाहर करने के लिए लागू नहीं होगा। इस मामले में कथित गलत कार्य के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया है, हालांकि शिकायत याचिका में स्वीकार किया गया है कि कार्य -कार्य ईआईएल के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, आपराधिक धमकी का आरोप सीधे अपीलकर्ता के खिलाफ है - ऐसे आरोपों का मूल्य या गुणवत्ता जो भी हो। इस प्रकार, इस कारण से कंपनी को शामिल न करने के एकमात्र आधार पर शिकायत मामले को प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अन्यथा हमने शिकायत और समन को रद्द करने के लिए अपने कारण बताए हैं, हमें इस बिंदु पर और अधिक विस्तार करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

21. हम तदनुसार आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और आपराधिक शिकायत मामले संख्या - 7990/2020 में 18.08.2021 को जारी किए गए समन आदेश को भी रद्द कर देते हैं। उपरोक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है। उक्त कार्यवाही के संबंध में सभी परिणामी कदम रद्द कर दिए जाएंगे।

हेडनोट्स दिव्या पांडे द्वारा तैयार किया गया:

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति दी गयी.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।